CNews सिटी चीफ

बिहार सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-107
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

आज का विचार

बलवान व्यक्ति की भी बुद्धिमानी इसी में है कि वह जानबूझ कर किसी को शत्रु न बनाए।

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

बिहार ,सोमवार 22 जुलाई 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

जमुई में शिक्षा विभाग के कार्यालय का हाल देखिये, बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे जहां-तहां फेंका मिला प्रश्नपत्र

चन्दन कुमार चौबे | सिटी चीफ

जमुई, बिहार में शिक्षा को बदहाली किसी से छुपी नहीं है। जमुई जिले के शिक्षा विभाग कार्यालय परिसर में लापरवाही और कुव्यवस्था की तस्वीर सामने आई है जहां 9वीं, 10वी और 12वी के हर महीने ली जानी वाली मासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के बंडल बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे जमीन पर जहां तहां फेंके हुए पाए गए। खुले आसमान के नीचे फेके गए बंडल को विभिन्न विद्यालयों के शिक्षको के द्वारा अपने विद्यालय कोड के अनुसार प्रश्नपत्र ढूंढते देखे गए। इस दौरान प्रश्न पत्र को ढूंढते शिक्षक परेशान

दिखे। हरेक शिक्षक को अपने स्कूल के लिए प्रश्नपत्र को ढूंढने में करीब एक घंटे का समय लग रहा था।हालांकि शिक्षक अपने परेशानी को बताने में डर रहे थे, कार्रवाई के डर से। शिक्षक दबी जुबान में कह रहे थे यह कोई तरीका का क्रेश्चन पेपर देने का। वहीं एक महिला शिक्षक ने कहा कल से परेशान है,क्रेश्चन पेपर खोजने में लगे हैं। दरसअल, 27 जुलाई से 9वी, 10वी और 12वी की मासिक परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा शामिल होने वाले हैं लेकिन उनके क्रेश्चन पेपर ही टीचर्स को नहीं मिल रहे हैं।शिक्षा विभाग के क्लर्क कौशलेंद्र कुमार ने बताया की क्रेश्चन पेपर को ले जा रहा है,नंबरिंग करके रख दिए है,फेका हुआ नही है।कोई भी टीचर परेशान नहीं है।सब क्रेश्चन पेपर ले जा रहा है।फेका हुआ नही है,हमलोग अभी इसे निकाले है।हमलोग सही तरीके से सुबह में ही रख दिए है। शिक्षा विभाग के कलर कौशलेंद्र कुमार अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है उनका कहना है कि सभी सही तरीके से रखा हुआ है फेंका हुआ नहीं है।

शादी के 3 दिन बाद दुल्हन पहुंच गई थाने

कहा-लड़का पसंद नहीं..एक पल भी नहीं रहूंगी साथ

चन्दन कुमार चौबे | सिटी चीफ

आरा, आरा के बिहिया में 17 जुलाई को पटना से बारात गई थी। तब धूमधाम के साथ शादी संपन्न हुई थी। लेकिन शादी के तीन दिन बाद ही दुल्हन थाने पर पहुंच गयी और यह कहने लगी की उसे लड़का पसंद नहीं है वो उसके साथ एक पल भी नहीं रहेगी। लड़की की बातें सुनकर परिजन और पुलिस कर्मी भी हैरान रह गये। पुलिस ने उसे काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो उनकी बात माने तक को तैयार नहीं थी। परिजन बेटी की जिद् के सामने सरेंडर पहले ही बोल चुके थे। हालांकि उन्होंने भी बेटी को खूब समझाया कि अब

तुम्हारी शादी हो चुकी है इस तरह की बात नहीं करो घर की इजत का भी ख्याल रखों लेकिन लड़की अपनी जिद् पर अड़ी थी उसने थानाध्यक्ष के सामने ही कह दिया कि वो किसी कीमत पर पति के साथ नहीं रह सकती। थाने में उस वक्त पति भी मौजूद था। दोनों पक्ष के लोग भी वहां उपस्थित थे जो लड़की बातें सुनकर हैरान रह गये। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करे और कहां जाएं दुल्हन तो जिद् पर ही अड़ी है कि वो पति के साथ नहीं रहेगी। लोग इस बात से हैरान हैं कि शादी हुए अभी तीन दिन ही हुए है आखिर यह नौबत क्यों आ गयी इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी होने लगी। परिजनों ने बताया कि शादी होने के बाद वो एक दिन भी खुशी से ससुराल में नहीं रही थी। शादी के चौथे दिन वो पति का घर पर छोड़कर थाने में चली गयी। थाने में जाकर कहने लगी मुझे पति पसंद नहीं है। किसी भी कीमत पर अब उसके साथ नहीं रहूंगी। उसकी बातें सुनकर पुलिसवाले भी दंग रह गये। फिर दुल्हन अपने पिता पर जबरन शादी करवाने का आरोप लगाया। वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था लेकिन परिवार वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी इसलिए वो इस शादी से खुश नहीं है। अब उसने पति से अलग होने के मन बना लिया है। वो अपने फैसले पर अडिग रहेगी। इतना कहने के बाद दुल्हन अपने मायके लौट आई। हालांकि शादी में जितने उपहार मिले थे उसे वो अपने साथ मायके ले गयी है। पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। वही दुल्हा और उनके परिवार वाले पटना के लिए रवाना हो गये हैं।

यूक्रेन के साथ युद्ध में हाजीपुर में बने जूते पहनकर उतर रही रूस की सेना

इस खासियत ने पुतिन को भी बनाया मुरीद

चन्दन कुमार चौबे | सिटी चीफ

हाजीपुर दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी में रूस की सेना की गिनती होती है। पिछले ढाई सालसे भी यादा समय से रसियन सेना यूक्रेन के साथ युद्ध कर रही है। लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध में रसियन सेना जिस जूते को इस्तमाल कर रही है। उसका निर्माण बिहार के हाजीपुर में किया जाता है। यहां संचालित कंपीटेंस एक्सपोर्टस में महिलाओं द्वारा इस विशेष जूते को तैयार किया जाता है। बताया गया कि माइनस 40 डिग्री में भी यह जूता कारगर है।

2018 से संचालित है कंपनी कंपीटेंस एक्सपोर्टस मूल रूप से कानपुर से जुड़ी है। 2018 में कंपनी के एमडी मो. दानिश ने बिहार के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से हाजीपुर में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। यहां कंपनी ऐसे जूते बना रही है जिसकी सप्लाई रशियन आर्मी को किया जाता है। कंपनी से अब-तक लाखों जोड़ी जूते निर्यात किए जा चुके हैं। कंपनी के जनरल मैनेजर शिव कुमार रॉय की माने तो अब तक रुस में 1.5 मिलियन जोड़ी जूतों की सप्लाई की जा चुकी है। जिसका मार्केट टर्न ओवर सौ करोड़ के करीब है।

माइनस 40 डिग्री में कारगर फैक्ट्री के प्रबंधक शिव कुमार रॉय के मुताबिक यहां बने जूते रूस की सेना के लिए बेहद कारगर है। रूस में तापमान माइनस 40 डिग्री तक होती है, और वहां यह जूता अपना काम बखूबी करता है। जूते के तलवे और सोल में अलग डिजाइन बनाया गया है। जूते हल्के और नॉन स्लीपरी होता है। जो कड़ी ठंडक के बीच भी अपना काम करता है। फैक्ट्री के प्रबंधक शिव कुमार रॉय के मुताबिक कंपनी रूसी सेना की जरूरतों के हिसाब से ऐस जूते बनाती है, जो हल्के और फिसलन-रोधी होते हैं।

70 फीसदी महिला वर्कर इस फैक्ट्री के अंदर वैशाली, पटना समेत राय के विभिन्न जिले के लगभग 300 के करीब महिला पुरुष वर्कर काम करते हैं। इनमें 70 फीसदी सिर्फ महिला वर्कर है जो रूसी सैनिकों को पहनने वाले जूते बनाती है।

100 करोड़ रुपए का जूता एक साल में हुआ निर्यात कंपनी के एमडी दानिश प्रसाद की महत्वाकांक्षा बिहार में एक विश्वस्तरीय कारखाना बनाना है। कंपनी ने पिछले साल 100 करोड़ के 15 लाख जोड़ी जूते निर्यात किए हैं। कंपनी की माने तो अगले साल इसे 50% बढ़ाने का लक्ष्य है। हाजीपुर की यह कंपनी रूस के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के बाजारों में लक्जरी, डिजाइनर और फैशन शू भी निर्यात करती है।

चिराग ने दिया हर सपोर्ट का भरोसा, बिहारियों के लिए गर्व की बात बिहार में अपराध और हत्या के बीच हम सब के लिए एक सुखद खबर है मेरे संसदीय क्षेत्र में निर्मित जूते का इस्तेमाल रूस की सेना अपने ढाल के रूप में कर रही है। ये बिहार , बिहारी और समस्त देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि अब विदेशों में भी बिहार के हुनर की चर्चाएं होगी। मैं स्थानीय सांसद के तौर पर जल्द ही कारखाने का दौरा करूंगा। वहां के स्थानीय कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा साथ ही आने वाले दिनों में इस उद्योग के विस्तारीकरण को लेकर जल्द ही रक्षामंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखूंगा। बिहार में इस प्रकार के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा।

बिहार में फिल्म की शूटिंग करने वाले निर्माता को मिलेंगे सब्सिडी और कई अन्य सुविधाएं

सरकार अनुदान के रूप में दो करोड़ से चार करोड़ तक की राशि प्रदान करेग

चन्दन कुमार चौबे | सिटी चीफ

पटना, सरकार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दे दी है. इससे राय में फिल्म निर्माण के काम को गति मिलेगी. इसके तहत 4 करोड़ तक की फिल्मों में 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. बिहार में काफी समय से फिल्म सिटी के निर्माण और फिल्म निर्माता को सब्सिडी दिए जाने की मांग की जा रही थी, बिहार के पड़ोसी रायों उत्तर प्रदेश और झारखंड में सरकार द्वारा निर्मित को सब्सिडी देने की

व्यवस्था की गई थी. जिसका नतीजा यह हुआ कि बिहार के जो निर्माता थे उत्तर प्रदेश और झारखंड में जाकर शूटिंग करना शुरू कर दिया. बिहार में शूटिंग बंद हो गई थी और यहां के फिल्म से जुड़े हुए लोगो की हालात बदल हो गई थी. परंतु आज नीतीश सरकार द्वारा फिल्म नीति 2024 की घोषणा करने के बाद बिहार के फिल्मकारो ने राहत की सांस ली है. आज शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत राय को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना, राय के ऐतिहासिक एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। साथ ही फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्मों के शूटिंग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को राय में फिल्मों के अधिकारिक फिल्मांकन हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान दिया जायेगा। अनुदान के रूप में दो करोड़ से चार करोड़ तक की राशि दी जाएगी जो पूरे देश में सर्वाधिक है.

वेंडर-अफसर गठजोड़ ! सरकारी स्कूलों में बेंच-डेस्क खरीद में भारी भ्रष्टाचार , भद्द पिटने के बाद तीन सप्लायर को किया गया आउट...दंड भी लगाया

चन्दन कुमार चौबे | सिटी चीफ

मोतिहारी, पूर्वी चंपारण(मोतिहारी) के सरकारी स्कूलों में बेंच-डेस्क के लिए भेजी गई करोड़ों की राशि का बंदरबांट हुआ है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्तर से बड़ा खेल हुआ। शिक्षा मंत्री के सामने सत्ताधारी विधायकों ने भ्रष्टाचार की पोल खोली तो वे भी हक्के-बक्के रह गए. जांच के आदेश हुए हैं. खुद को घिरते देख, अब जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मानने लगे हैं कि बेंच-डेस्क की आपूर्ति में बड़ी गड़बड़ी हुई है. मीडिया में खबर आई, सत्ताधारी विधायकों ने आपत्ति दर्ज की, इसके बाद जांच की खानापूर्ति शुरू हुई है. जिला शिक्षा कार्यालय ने स्वीकार किया है कि तीन वेंडरों ने मानक के अनुरूप बेंच-डेस्क की सप्लाई नहीं की. लिहाजा उन पर दंड लगाया गया है. साथ ही उन तीनों वेंडरों को बेंच-डेस्क खरीद से अलग कर दिया है.

तीन वेंडरों को किया गया आउट..दंड भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मोतिहारी ने इस संबंध में सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा है. कहा है कि तीन वेंडरों से बेंच डेस्क न लें. इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने आज 20 जुलाई को पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी विद्यालयों में बेंच डिस्क का क्रय किया जाना है. इस आलोक में 18 मई को आपूर्तिकर्ताओं से बेंच डेस्क क्रय करने के लिए आदेश निर्गत किया गया था. विद्यालयों को आपूर्ति की गई बेंच-डेस्क के निरीक्षण के क्रम में

गड़बड़ी मिली, मानक के अनुरूप सप्लाई नहीं होने पर तीन एजेंसी (धीरज इंटरप्राइजेज तुरकौलिया, शिन्नी इंटरप्राइजेज अरेराज और आदर्श इंटरप्राइजेज अरेराज) से स्पष्टीकरण पूछा गया था .इसके बाद इन पर दंड अधिरोपित किया गया है. ऐसे में इन तीनों एजेंसियों (धीरज इंटरप्राइजेज शिन्नी इंटरप्राइजेज और आदर्श इंटरप्राइजेज से किसी तरह का बेंच- डेस्क का क्रय नहीं करें. अगर ऐसा करते हैं तो उसके भुगतान की सारी जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधान की होगी.

खुद को फंसते देख कंप्यूटर ऑपरेटर को किया आउट ! जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मोतिहारी ने 16 जुलाई को आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है की जिला कार्यकारिणी समिति सर्व शिक्षा अभियान पूर्वी चंपारण के निर्णय के आलोक में दिवेश कुमार (डाटा एंट्री ऑपरेटर) 8 मार्च 2008 से दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत हैं. वर्तमान में कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की उपलब्धता, वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है. इस कारण अब दिवेश कुमार की आवश्यकता नहीं है. ऐसे में पत्र निर्गत होने की तिथि से दिवेश कुमार की सेवा नहीं ली जाएगी. डीईओ कार्यालय ने अचानक दिवेश कुमार को क्यों हटाया क्या 16 तारीख से पहले कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं थे अचानक ऑपरेटर की उपलब्धता हो गई अगर दिवेश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर रहते दूसरा काम कर रहा था तो क्या इसकी जानकारी डीईओ को नहीं थी कई शिकायतें भी मिली थी, तब डीईओ-डीपीओ(स्थापना) ने क्यों नहीं कार्रवाई की अब एक्शन लेने की नौबत क्यों आई दरअसल, इसके पीछे बड़ा खेल है. विभागीय सूत्र यह बता रहे हैं कि अंत-अंत तक डीपीओ स्थापना की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही थी.

लाभ लेने वाले हाकिमों पर कब होगा एक्शन पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस आदेश से कई सवाल उठ रहे हैं. कहा तो यह भी जा रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर तो सिर्फ मोहरा था, लाभ तो हाकिम ले रहे थे. तभी तो वे हटाने को तैयार नहीं थे. जिलाधिकारी के सख्त रूख के बाद आखिरकार दिवेश कुमार को कार्य मुक्त किया गया है. आगे क्या होगा, जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई होगी क्यों कि दैनिक परिश्रम करने वाला कर्मी इतना ताकतवर नहीं हो सकता. बिना अफसर की सहमति के वो कैसे अब तक काम कर रहा था बता दें, पूर्वी चंपारण जिले में सरकारी स्कूलों में बेंच-डेस्क व अन्य विकास कार्यों के भेजी गई करोड़ों की राशि का बंदरबांट किया गया है. जिम्मेदार अफसरों ने खास को काम देकर पैसे का बंदरबांट किया है. कहा जा रहा है कि इसमें जिले के पूर्व और वर्तमान के अधिकारी शामिल हैं. सत्ताधारी विधायकों ने भी शिक्षा मंत्री से कंप्लेन किया है. जांच के आदेश भी हुए हैं,लेकिन रिजल्ट शून्य है.

मुखिया और वार्ड सदस्यों के फंड में कटौती

अब बिना टेंडर पंचायतों में नहीं होंगे कोई भी विकास कार्य, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला

पटना, बिहार में एनडीए की सरकार ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पंचायत की विकास योजनाओं में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर दी है। अब बिना टेंडर पंचायतों में किसी तरह के विकास कार्य नहीं किए जाएंगे। दरअसल, बिहार में पंचायत स्तर पर कराए जाने वाले विकास कार्यों को पहले मुखिया और वार्ड सदस्य अपने स्तर से काम कराते थे। विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त मुखिया और वार्ड सदस्यों के पर कतर दिए हैं और उनके अधिकारों में बड़ी कटौती कर दी है। नितीश कुमार ने अब पंचायतों में होने वाले किसी भी विकास कार्य के लिए टेंडर जरूरी कर दिया है। बिना टेंडर की प्रक्रिया पूरी किए मुखिया और वार्ड सदस्य कोई भी विकास का काम अपने स्तर से नहीं करा सकेंगे। सरकार ने मुखिया और वार्ड सदस्य के अधिकारों में कटौती कर दी है। बिहार सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल बनाई है, जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब मुखिया या वार्ड सदस्य योजनाओं के कार्यान्वयन में मनमानी नहीं कर सकेंगे।

बेटी को प्रेमी के साथ कमरे में आपत्तिजनक हाल में देखा

बेटों-देवर के साथ मिलकर दोनों का मार डाला, गंगा में फेंका शव

चन्दन कुमार चौबे | सिटी चीफ | हाजीपुर, जिले के देसरी थाना अंतर्गत गुम हुए व्यक्ति की हत्या की सफल उद्वेदन पुलिस ने किया है। बीते 17 जून को देसरी थाना को आवेदन प्राप्त हुआ कि दिनांक 29/5/23 को ग्राम मजलिसपुर निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र प्रभात कुमार उर्फ निखिल कुमार और वापस लौट कर नहीं आया है। इस संदर्भ में देसरी थाने में मामला दर्ज पुलिस अधीक्षक वैशाली के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया गठित टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई की सुरेंद्र सिंह के पुत्र प्रभात कुमार का खुसरूपुर थाना क्षेत्र निवासी गीता देवी की पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसमें दोनों को लड़की की माँ भाई के द्वारा आपत्तिजनक स्थिति में देखा लिया गया था. जिससे गुस्से में आकर लड़की की मां गीता देवी एवं दोनों भाई एवं चाचा के द्वारा दोनों की हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया था। पूरे घटना में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है गिरफ्तार आरोपी पटना जिले के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के हरदास बीघा गांव निवासी लाल बाबू राय के पत्नी गीता देवी पुत्र संदीप कुमार सुशील कुमार नगीना राय के पुत्र बृजेश्वर राय को गिरफ्तार किया गया है।

करप्शन का खेल ! कंप्यूटर ऑपरेटर को तो हटा दिया...भ्रष्टाचार के खेल में शामिल अधिकारियों पर कब होगा एक्शन

शिक्षा विभाग में करोड़ों की राशि का हुआ है बंदरबांट

चन्दन कुमार चौबे | सिटी चीफ |

पटना, पूर्वी चंपारण(मोतिहारी) के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बड़ा खेल चल रहा है. एक मीडिया ने जब खेल का खुलासा किया तो बड़े अधिकारी भी बेनकाब हुए. शिक्षा मंत्री के सामने सत्ताधारी विधायकों ने भ्रष्टाचार की पोल खोली तो वे भी हक्के-बक्के रह गए. जांच के आदेश हुए हैं, लेकिन जांच की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है. इन सबके बीच डीईओ ने एक कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर दी है. ऑपरेटर की सेवा क्यों समाप्त की गई, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में पत्र में उल्लेख किया है. जो कारण बताये हैं, उससे ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं. यानि अदना सा कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर विभाग के हाकिमों अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश की है. हकीकत यही है पूरे खेल में ऑपरेटर तो सिर्फ मोहरा था, भ्रष्टाचार का खेल तो कोई और खेल रहा था. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मोतिहारी ने 16 जुलाई को आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है की जिला कार्यकारिणी समिति सर्व शिक्षा अभियान पूर्वी चंपारण के निर्णय के आलोक में दिवेश कुमार (डाटा एंट्री ऑपरेटर) 8 मार्च 2008 से दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत हैं. वर्तमान में कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की उपलब्धता, वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है. इस कारण अब दिवेश कुमार की आवश्यकता नहीं है. ऐसे में पत्र निर्गत होने की तिथि से दिवेश कुमार की सेवा नहीं ली जाएगी. डीईओ कार्यालय ने अचानक दिवेश कुमार को क्यों हटाया क्या 16 तारीख से पहले कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं थे अचानक ऑपरेटर की उपलब्धता हो गई अगर दिवेश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर रहते दूसरा काम कर रहा था तो क्या इसकी जानकारी डीईओ को नहीं थी कई शिकायतें भी मिली थी, तब डीईओ-डीपीओ(स्थापना) ने क्यों नहीं कार्रवाई की अब एक्शन लेने की नौबत क्यों आई दरअसल, इसके पीछे बड़ा खेल है. विभागीय सूत्र यह बता रहे हैं कि अंत-अंत तक डीपीओ स्थापना की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही थी.

लाभ लेने वाले हाकिमों पर कब होगा एक्शन पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस आदेश से कई सवाल उठ रहे हैं. कहा तो यह भी जा रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर तो सिर्फ मोहरा था, लाभ तो हाकिम ले रहे थे. तभी तो वे हटाने को तैयार नहीं थे. जिलाधिकारी के सख्त रूख के बाद आखिरकार दिवेश कुमार को कार्य मुक्त किया गया है. आगे क्या होगा, जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई होगी क्यों कि दैनिक परिश्रम करने वाला कर्मी इतना ताकतवर नहीं हो सकता. बिना अफसर की सहमति के वो कैसे अब तक काम कर रहा था बता दें, पूर्वी चंपारण जिले में सरकारी स्कूलों में बेंच-डेस्क व अन्य विकास कार्यों के भेजी गई करोड़ों की राशि का बंदरबांट किया गया है. जिम्मेदार अफसरों ने खास को काम देकर पैसे का बंदरबांट किया है. कहा जा रहा है कि इसमें जिले के पूर्व और वर्तमान के अधिकारी शामिल हैं. सत्ताधारी विधायकों ने भी शिक्षा मंत्री से कंप्लेन किया है. जांच के आदेश भी हुए हैं,लेकिन रिजल्ट शून्य है.